

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे०एन०मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 106/2014 (225 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर- 2014/00293

उनवानी :-

1- श्रीनिवास पुत्र बैनी जाति ब्रह्मण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट-----

बनाम

- 1- अनिल पुत्र मुरारी जाति ब्रह्मण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।
- 2- विनय पुत्र मुरारी जाति ब्रह्मण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।
- 3- सन्तोष पुत्र मुरारी जाति ब्रह्मण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।
- 4- सीमा पुत्री मुरारी जाति ब्रह्मण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।

रेस्पों-----

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर
भरतपुर दिनांक 04.01.2013 मु०न० 34/2007
उनवानी मुरारी बनाम श्रीनिवास।

उपस्थिति:-

- 1- वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुन्तल एड०
- 2- वकील रेस्पों श्री हरी दत्त शर्मा एड०

निर्णय

दिनांक 03.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय नें जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वह इजराय की कार्यावाही पूरी होने के पश्चात जारी किया है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थागण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश 4.01.2013 को पारित किया गया है जबकि इजराय 15.12.2004 को ही हो चुकी थी और डिक्री में इजराय के पश्चात प्रा.पत्र पेश नहीं किया जा सकता केवल अपील की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय नें अपने आदेश में ख.न. 66 एवं 69 को भी शामिल कर लिया है जबकि निर्णय में इसका कोई उल्लेख नहीं था अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय का आदेश माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नहीं है और यह आदेश उभय पक्ष को सुनवाई का मौका देने के उपरान्त पारित किया है अतः अपील खारिज की जावे।

बहस उभय पक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से यह सिद्ध है कि वकील अपीलार्थी ने ख.न. 66 व 69 को शामिल कर लेने बाबत आक्षेप किया है जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी के दो निर्णय इस पत्रावली में संलग्न है जिसमें से अपील संख्या 343/2001 में ख.न. 646 बाबत निर्णय पारित किया है जबकि 346/2001 में ख.न. 66 व 69 बाबत आदेश किया गया है इस प्रकार अपीलार्थी का यह तर्क कि राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित कर दिया है, तथ्यों के परे प्रकट होता है अतः अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलार्थी तथ्यों के परे होने के कारण खारिज की जाती है।

सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर